Economic Planning & its techniques

आयोजन एक तकनीक, एक साध्य की प्राप्ति का साधन और वह साधन है जो केन्द्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ~~की~~ पूर्वनिश्चित तथा सुस्पष्ट लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करता है। आर्थिक आयोजन को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएँ दी है।

प्रो० रॉबिन्स के अनुसार "आर्थिक आयोजन उत्पादन तथा विनिमय की निजी क्रियाओं का सामूहिक नियंत्रण का प्रतिस्थापन है।"

हेक के अनुसार "आयोजन का अर्थ है "केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा उत्पादकीय क्रिया का निर्देशन।"

डिकन्सन के अनुसार आयोजन का अर्थ है "इस विषय में प्रमुख आर्थिक निर्णय करना कि किस वस्तु का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाय, कब और कहाँ उत्पादन हो और समस्त अर्थव्यवस्था के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर निर्णायक प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार उस उत्पादन को कैसे विभाजित किया जाए।

इसप्रकार यद्यपि इस विषय में अर्थशास्त्रियों का एक मत नहीं है फिर भी आर्थिक आयोजन का मतलब "समय की एक निश्चित अवधि के भीतर निश्चित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा अर्थव्यवस्था का आयोजित नियन्त्रण तथा निर्देशन है।

~~भारत जैसे अर्धविकसित देशों में आयोजन की प्रमुख~~

लेविस महोदय ने योजना को 6 दृष्टिकोण से स्पष्ट किया जो निम्नलिखित है:—

1. शहर एवं देश नियोजन जिससे भौगोलिक क्षेत्रों का निर्धारण होता है।
2. योजना का अर्थ है कि सरकार भविष्य में कितना मुद्रा व्यय करेगी।
3. योजना का अर्थ कोटा द्वारा साधनों का आवंटन होता है तथा केन्द्रीय आज्ञानुसार उत्पाद का वितरण होता है।
4. योजना का अर्थ देश के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन लक्ष्य को निर्धारित करना है।
5. योजना का अर्थ देश का कुल उत्पादन लक्ष्य ~~और किसी~~ निर्धारित करना है।
6. योजना का अर्थ उत्पादन लक्ष्य को निजी उपक्रमों पर लागू करना है।

लेविस के अन्तिम तीन दृष्टिकोण आर्थिक योजना के समान है।

निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना की आवश्यकता होती है रणनीति तैयार होती है जो निम्नलिखित है —

1 गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ना — अर्द्धविकसित राष्ट्रों में गरीबी का दुश्चक्र, बजार के अपूर्णता, अर्द्धविकास आदि कई तरह के दुश्चक्र एक साथ चलते रहते है जिससे प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न रहता है, उत्पादन क्षमता निम्न रहती है, बाजार का आकार निम्न रहता है। इसे निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है।

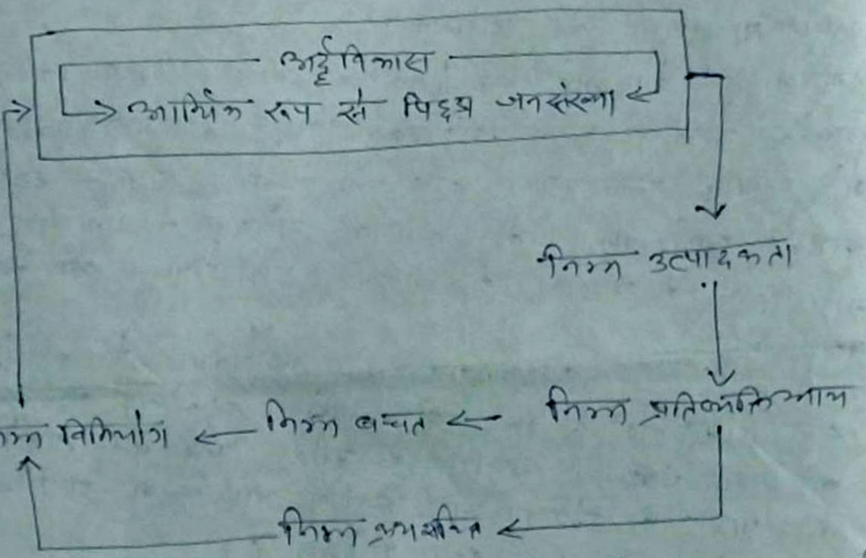

इस दुश्चक्र को तोड़ने के लिए योजना के द्वारा बहुत बड़ी रकम व्यय करने की जरूरत होती है जिसे क्रान्तिक न्यूनतम प्रयास या जोरदार धक्का "Big Push" कहा जाता है। क्योंकि मात्रा में विनियोग में वृद्धि अकेले निजी क्षेत्र नहीं कर सकते है इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में भारी विनियोग की जरूरत पड़ती है जो कि योजना के द्वारा ही संभव है।

2. औद्योगिकरण — आर्थिक विकास के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। औद्योगिक क्रान्ति जितनी जल्द आरम्भ हो जाए उतने ही तेजी से आर्थिक विकास संभव होता है। आर्थिक योजना को लागू कर औद्योगिकरण की गति को तीव्र किया जाता है। योजना के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में आधारभूत तथा बड़े उद्योगों को स्थापित किया जाता है।

3. आर्थिक एवं सामाजिक संरचना – भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का आधार कमजोर है। बिजली संकट, अपर्याप्त सड़क, अपर्याप्त बंदरगाह सुविधा, संचार व्यवस्था का अविकसित ढाँचा आदि समस्या बिना योजना को लागू किये दूर नहीं की जा सकती है। सिंचाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की व्यवस्था असंतोषजनक है। इसलिए आर्थिक योजना के द्वारा अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का निर्माण तेजी से करने के लिए योजना की आवश्यकता पड़ती है।

4. पूर्णरोजगार की प्राप्ति हेतु – अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, अर्द्धरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी की समस्या रहती है। योजना के अन्तर्गत मानवशक्ति योजना बनाकर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। जे. एस. उप्पल ने अदृश्य बेरोजगारी को निम्न रेखाचित्र से दर्शाया है —

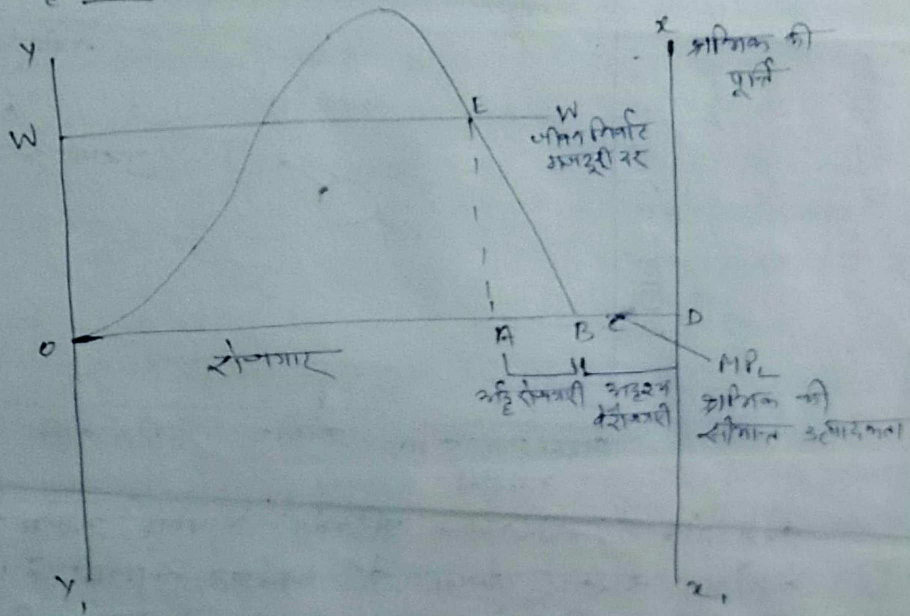

चित्र में BC + CD = BD श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक है इसलिए BD श्रमिक को अदृश्य बेरोजगारी कहा जायेगा। AB श्रम की पूर्ति को अर्द्धरोजगारी मानेंगे क्योंकि इनका उत्पादन स्तर निश्चित रूप से मजदूरी दर से कम रहता है। इसलिए BD श्रमिक को अतिरिक्त

से हटाने पर कुल उत्पादन को कम नहीं बता रहा है। योजना की आवश्यकता इस बात के लिए होती है कि अदृश्य बेरोजगारी वाले क्षेत्रों तथा जिलों की पहचान कर रोजगार कार्यक्रम द्वारा सरकारी काम बढ़ाकर इन क्षेत्रों को विकसित किया जाय तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हेतु योजनाएं लागू की जाए। भारत में ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आदि इसी दिशा में उठाये गए कदम है।

5. कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता —

कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कृषि योजना की आवश्यकता होती है। अच्छे बीज, रासायनिक खाद, अच्छी तकनीकी का कृषि में उपयोग बढ़ाने के लिए योजना की आवश्यकता होती है। नवीन कृषि तकनीक से उत्पादन में चमत्कारपूर्ण वृद्धि होती है जिसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है —

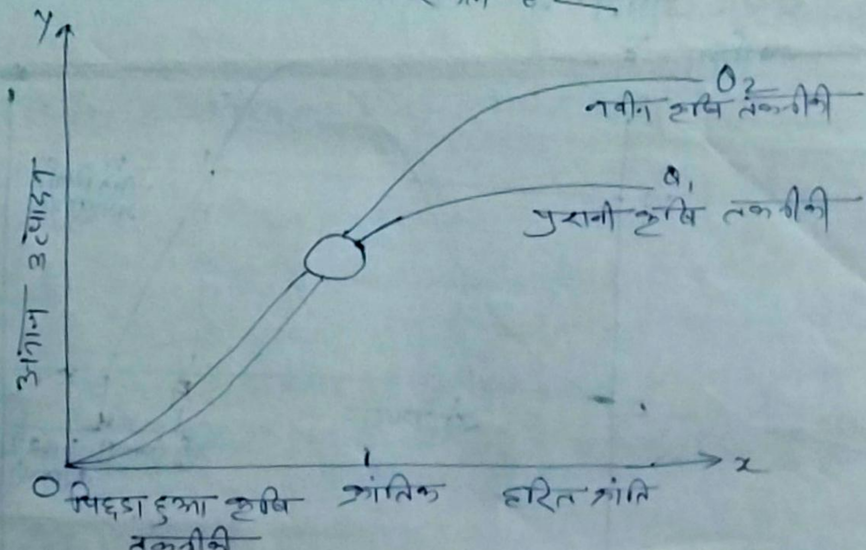

कृषि क्षेत्र में संस्थागत परिवर्तन के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम सरकार योजना के अन्तर्गत चलाती है। योजना के द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान आदि को प्रोत्साहन दिया जाता है।

6. आय की वितरण की विषमता में कमी लाने हेतु —

अगर अर्थव्यवस्था में गरीबी तथा आय की वितरण की विषमता दोनों है तब एक मात्र उपाय योजना के द्वारा

आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि करना होता है। गरीबी तथा आय के वितरण की विषमता को अमर्त्य सेन ने एक साथ चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है जो निम्नलिखित है —

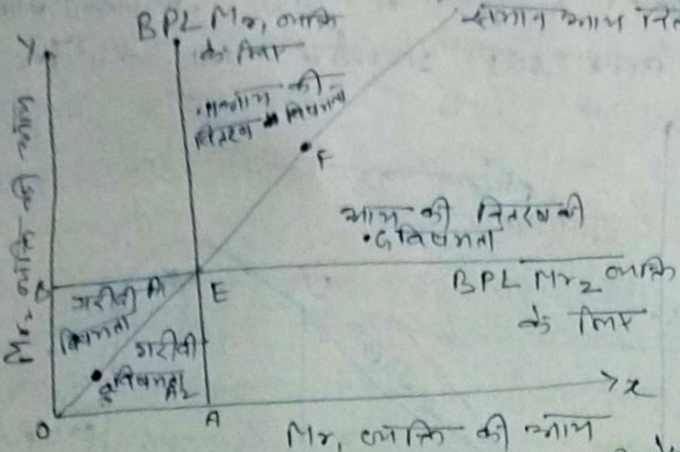

अमर्त्य सेन ने Mr_1 तथा Mr_2 को व्यक्तियों को समान में गरीबी रेखा के नीचे तथा गरीबी को A_1 तथा A_2 बिन्दु द्वारा दर्शाया है जबकि आर्थिक संवृद्धि के कारण गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आय के वितरण की विषमता H तथा G बिन्दुओं से प्रदर्शित किया गया है। गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आय का समान वितरण की प्राप्ति F बिन्दु पर प्रदर्शित किया गया है। समाज योजना के द्वारा O से E तथा E से F की ओर प्रस्थान करे इसके लिए राज्य को प्रत्यक्ष जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इसके लिए राजकोषीय नीति से विषमता दूर होगी और मौद्रिक नीति से आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि लायी जायेगी।

7. बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं का विकास — आर्थिक योजना के अन्तर्गत बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं का क्रमबद्ध विकास होता है जिसके द्वारा बचत का संग्रहण किया जाता है इनसे पूंजी निर्माण तथा विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। वित्तीय संस्थाओं में कई प्रकार के जोखिम होते हैं जैसे साख जोखिम, तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम, करेंसी जोखिम आदि इन सभी से निपटने के लिए आर्थिक नियोजन ही जोखिम मैनेजमेन्ट का तरीका बतलाता है।

8. जनसंख्या नियंत्रण — जनसंख्या वृद्धि जब तेजी से होती है तथा अर्थव्यवस्था जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आ जाती है

किसी देश में आर्थिक योजना के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण योजना लागू की जाती है ताकि 'जनसंख्या जाल' से अर्थव्यवस्था को निकाला जा सके। नेलसन के द्वारा 'जनसंख्या जाल' को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है –

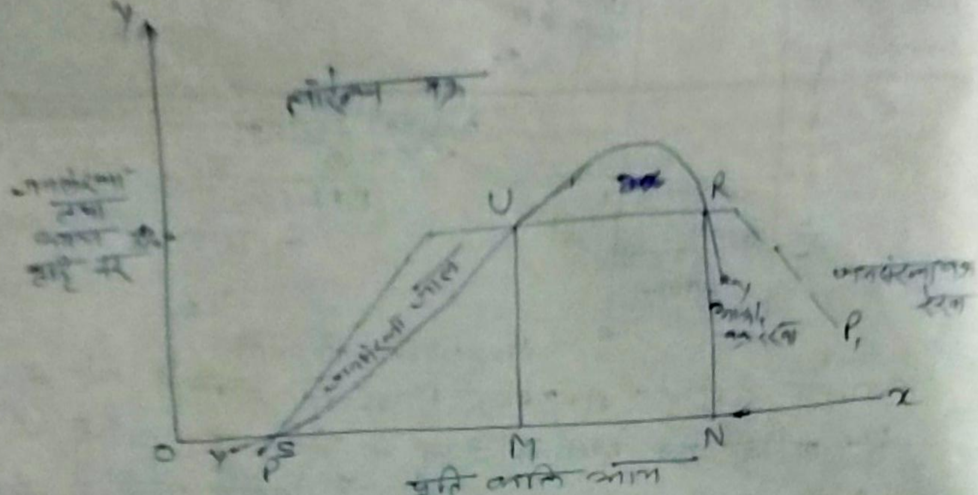

चित्र में S बिन्दु पर जनसंख्या वृद्धि दर तथा आय वृद्धि दर शून्य है। चित्र में S तथा M के बीच जनसंख्या वृद्धि दर आय वृद्धि दर से ऊँची है जिसे जनसंख्या जाल कहा जाता है। अगर आर्थिक योजना के द्वारा प्रति व्यक्ति आय M से N तक बढ़ा दिया जाए तब अर्थव्यवस्था 'जनसंख्या जाल' से निकल जाएगा। M N मात्रा में वृद्धि भारी धक्का 'Big Push' का कार्य करती है जो आर्थिक योजना में सार्वजनिक निवेश में भारी वृद्धि के द्वारा संभव होता है।

9. भुगतान शेष को अनुकूल बनाना – आर्थिक नियोजन के द्वारा विदेशी मुद्रा का बजट, निर्यात योजना एवं आयात योजना में समन्वय स्थापित कर भुगतान शेष को अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

10. क्षेत्रीय विषमता में कमी – आर्थिक योजना के द्वारा देश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमता को कम किया जाता है। क्षेत्रीय योजना के द्वारा क्षेत्र विशेष में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि की जाती है।

11. आर्थिक सुरक्षा – आर्थिक नियोजन अन्तर्गत आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। आर्थिक सुरक्षा के अन्तर्गत सरकारें शोषण के विरुद्ध कानून बनाना, बीमा योजना, भविष्य निधि योजना, पेंशन आदि योजनाएँ लागू करती हैं इससे कार्यकुशलता के साथ साथ समाज कल्याण में भी वृद्धि होती है।

12. साधनों का उचित उपयोग – अल्पविकसित देशों के ~~साधनों की कमी नहीं रहती उनका उचित उपयोग शिक्षा के अभाव में नहीं हो पाता~~ इसलिए आर्थिक नियोजन से साधनों का उचित उपयोग होता है। तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी की कमी के कारण प्राकृतिक साधनों एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। साधनों के उचित उपयोग के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का इकट्ठा विकास करना जरूरी होता है।

इस प्रकार ~~आर्थिक~~ उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बावजूद आर्थिक योजना का महत्व घटा नहीं है। आयोजन एक ऐसा यन्त्र है जिसके बिना उच्च स्तर पर विकास संभव नहीं है।

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College